B.Ed – 1st Year **Nakul Sah**

Gender, School and Society **Assistant Professor**

Course- 6

Lecture – 21

Unit – 2

Schooling of girls

बलिकाओं की विद्यालयी शिक्षा

विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक और दोषपर्ण है तथा बालिकाओ की अभिरूचियों का ध्यान भी पाठ्यक्रम मे नही रखा जाता है जिससे बालिकाओं में पढ़ाई के प्रति अरूचि की भावना जाग्रत हो जाती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपर्ण है जिस कारण शिक्षा का सम्बन्ध अव्यावहारिक होने से शिक्षा पर हुआ समय तथा पैसे का व्यय जिसकी भरपाई नहीं हो पाती है। अतः बालकों की शिक्षा की अपेक्षा बालिका शिक्षा ही नहीं, अपितु इस लिंग के प्रति ही लोगों में दुर्भावना व्याप्त हो जाती है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्याप्त दोष निम्न प्रकार हैं–

1. दोषपूर्ण पाठ्यक्रम
2. अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य
3. दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ
4. अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या

5. बालिका विद्यालयों का अभाव
6. विद्यालयों का दूर होना
7. व्यावसायिक पाठशालाओं का अभाव
8. लैंगिक विभेद

शिक्षा के उद्देश्य भारतीय समाज तथा आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के कारण भी बालिकाओं के लिए शिक्षा उद्देश्यविहीन मानी जाने लगी है। शिक्षण विधियाँ निष्क्रिय तथा एकपक्षीय हैं जिस कारण शिक्षा ग्रहण करने में बालिकाओं को रूचि नहीं होती है।

बालिकाओं के विधालय छोड़ने (ड्राप आउट)के कारण

भारत में करीब आठ करोड़ बच्चे विभिन्न कारणों से प्राथमिक स्तर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं जिनमें लड़कियों की संख्या अधिक होती है। महिलाओं और बच्चो के लिए बनी नीतियों और कार्यक्रमों से सबंधित संगोष्ठी में यूनीसफे के भारत प्रतिनिधि जॉर्ज आर्सेनॉल्ट ने कहा कि भारत में करीब आठ करोड़ बच्चे प्राथमिक स्तर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे ड्राप आउट बच्चों में लड़को की अपक्षेा लड़कियों की संख्या अधिक होती है। कक्षा एक से पांच तक लड़कियों की अपेक्षा लडक़ों की ड्राप आउट दर अधिक है। कक्षा एक से आठवीं तक लड़कियो की ड्रॉप आउट दर लडक़ों के मुकाबले अधिक है। यानी माता–पिता बेटों की अपेक्षा बेटियों को बड़े उत्साह के साथ प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने देते हैं लेकिन कक्षा आठ तक पहुंचते–पहुंचते यह उत्साह कम हो जाता है। समाज में असुरक्षित माहौल एवं विभिन्न कुरीतियों के कारण आठवीं या उससे बडी़ कक्षा की पढ़ाई के लिए उनके परिवार वाले मना करते हैं। करीब 35

प्रतिशत लड़कियों का मानना है कि कम उम्र में शादी होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। शारीरिक उत्पीड़न के खिलाफ कानून बन जाने के बावजूद पिटाई के डर से भी लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं आठवीं से दसवीं कक्षा के बीच पढाई छोड़ चुकी लगभग 55 प्रतिशत लड़कियों का मानना है कि शिक्षको द्वारा सजा के कारण उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। एक बड़ा आर्थिक पहलू यह भी सामने आया कि करीब 75 फीसदी लड़कियों को गरीबी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सयुंक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि बालिका शिक्षा बच्चों के जीवन में सीधे तौर पर जुड़ी है भारत में महिलाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराकर लाखो बच्चों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2012 में भारत के पांच वर्ष से कम आयु के करीब एक करोड़ 41 लाख बच्चे मौत के मुंह में समा गए। यदि भारत में सभी महिलाओं ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की होती तो उक्त मौतों में 13 फीसदी तक कमी की जा सकती थी और यदि सभी महिलाओं ने दसवीं तक पढाई पूरी की होती तो होने वाली मातों में करीब 60 फीसदी की कमी हो सकती थी।

विधार्थियों के विद्यालय छोड़ने (ड्राप आउट) के कारण

विधार्थियों के विद्यालय छोड़ने के निम्न कारण हैं–

★ लड़कियों को बोझ की तरह समझना

★ माता–पिता का अशिक्षित होना

★ पारिवारिक आय कम होना

★ समाज व परिवार में चेतना का अभाव

★ गरीबी केवल लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान देना

★ लड़कियों की जल्दी शादी करने के कारण पढ़ाई छूट जाना

★ लडक़ा घर का सहारा बनेगा और लडक़ी पराया धन होने के कारण दूसरे घर को रौशन करेगी।

★ परिवार में पढ़ाई के लिए बुनियादी सुविधा का अभाव जैसे स्थान व प्रकाश तथा पुस्तक पेंसिल आदि।

★ अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जाकर आर्थिक उद्यम में लग जाते हैं, लड़कियों को शिक्षा में और भी बाधाएं हैं, पढ़–लिख कर भी तो रोटियां ही पकानी हैं। यह मानसिकता सबसे बडी़ बाधा है

★ एक औसत परिवार में लडक़ों की अपेक्षा लड़कियों को घर पर भी अधिक काम करना पड़ता है, उनकी शिक्षा में परिवार का अपक्षेाकृत उत्साह भी कम रहता है, पढ़ाई के लिए घर से सुविधाएं भी कम रहती हैं।

★ बड़े परिवार में छोटे भाई बहनों को पालने के कारण।

विद्यालयों में उपस्थिति कम होने की वजह

- शिक्षकों की भारी कमी
- भवन न होना
- आधारभूत सुविधाओ ंकी कमी
- लड़कियों के लिए शौचालय नहीं होना
- सचांर प्रौद्योगिकी का अभाव।
- मध्याह्न भोजन से पढ़ाई मे ंबाधा
- पयेजल व बैठन की व्यवस्था नहीं होना
- निजी विद्यालयों की ओर बढ़ता मध्यम वर्ग

● सरकारी विद्यालयों से मिशनरी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में बच्चो का लगातार पलायन

शिक्षा के गिरते स्तर पर एक शिक्षाविद ने कहा है कि अनक योजनाओं के बावजूद प्राथमिक स्कूल के बच्चों का स्तर लगातार घट रहा है। सरकारी आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि समय–समय पर इन विद्यालयों में बच्चों की सख्या में बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन गुणवत्ता क्या है, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून का चार साल गुजर जाने के बाद भी वह पूरी तरह से सफल नहीं रहा है। शिक्षा में फैलते भ्रष्टाचार की हालत यह है कि कई भूतपूर्व मंत्री जेल में हैं। यह हालत किसी एक प्रदेश की नहीं है, अपितु अधिकतर प्रदेशों में ऐसे लोगों का बोलबाला है। ऐसे में जब बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे तो छोटे अधिकारियों से क्या उम्मीद रखी जाए। उनका मानना है कि अगर उच्च पद पर आसीन राजनेता एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी। साथ ही अगर सरकार को विद्यालयों की स्थिति सुधारनी है तो वह स्थानीय स्तर पर जनता का सहयोग लें और उन्हें बताए कि स्कूल उनका है और उन्हें ही सभांलना है। सरकार द्वारा इन विद्यालयों को पर्याप्त धन मुहैया कराया जाए। प्रतिदिन निरीक्षण की व्यवस्था हो एवं शिक्षा के नाम पर लाक लुभावन योजनाओं के द्वारा छात्रों को लुभाया न जाए।

to be continued .....